



वर्ष 46 अंक 5
31 मई 2016

मेवाड़ चेम्बर पत्रिका

(मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री का मासिक पत्र)

उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़
राजसमन्द एवं भीलवाड़ा का सम्भागीय चेम्बर



केन्द्रीय कपडामंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार एवं फूड प्रोसेसिंग राज्यमंत्री साध्वी निरंजना ज्योति
झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा चेम्बर की ओर आयोजित सम्पर्क बैठक में।

मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री

मेवाड़ चेम्बर भवन, नागौरी गार्डन, भीलवाड़ा (राज.) 311 001 फोन : 01482-220908, 238948

Email : mcci@mccibhilwara.com Visit us : www.mccibhilwara.com

1 जून 2016 को मेवाड चेम्बर की ओर से आयोजित सम्पर्क बैठक



कपडामंत्री माननीय श्री संतोष कुमार गंगवार का स्वागत करते हुए चेम्बर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री दिनेश नौलखा।



कपडामंत्री माननीय श्री संतोष कुमार गंगवार का स्वागत करते हुए चेम्बर के मानद महासचिव श्री सूर्य प्रकाश नाथानी।



केन्द्रीय फूड प्रोसेसिंग राज्यमंत्री माननीया साध्वी निरंजना ज्योति का स्वागत करते हुए उपाध्यक्ष श्री आर एल नौलखा एवं श्री जे सी लड्डा।



झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अर्जुन मुंडा का स्वागत करते हुए उपाध्यक्ष श्री एस एन मोदानी।



समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथि एवं चेम्बर के सदस्यगण।

MEWAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Mewar Chamber Bhawan, Nagori Garden

Bhilwara 311 001 (Raj.) ☎ 01482-220908 Fax : 01482-238948

✉ mcci@mccibhilwara.com 🌐 www.mccibhilwara.com

OFFICE BEARERS

	OFFICE	MOBILE
President Mr. Anil Mansinghka anil@shardagroup.net	01482-233800	98290-46101
Sr. Vice President Mr. Dinesh Nolakha dinesh@nitinspinners.com	01482-286111	98281-48111
Vice Presidents Mr. N. N. Jindal jindamarblepl@gmail.com Mr. J. K. Bagrodia jkbagrodia1@gmail.com Mr. P. K. Jain praveen.jain@vedanta.co.in	01472-240148	94147-34834
	01482-242435	94141-10754
	01483-229011	99280-47578

	OFFICE	MOBILE
Hony. Secretary General Mr. S.P. Nathany mcci@mccibhilwara.com	220908, 238948	94141-12108
Hony. Joint Secretary Mr. R. K. Jain rkjainbhilwara@gmail.com	01482-225844	94141-10844
Hony. Treasurer Mr. Deepak Agarwal deepak@babacollection.com	01482-241600	98290-67400
Executive Officer Mr. M.K.Jain mcci@mccibhilwara.com	220908	94141-10807

AFFILIATION

At the International Level : International Chamber of Commerce, Paris (France)

At the National Level : Federation of Indian Chamber of Commerce & Industry, (FICCI) New Delhi
Indian Council of Arbitration, New Delhi
National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development (NIESBUD), New Delhi.

Confederation of All India Traders, New Delhi

At the State Level : Rajasthan Chamber of Commerce & Industry, Jaipur.
: The Employers Association of Rajasthan, Jaipur.
: Rajasthan Textile Mills Association, Jaipur

REPRESENTATION IN NATIONAL & STATE LEVEL COMMITTEES

All India Power loom Board, Ministry of Textile, Govt. of India, New Delhi

National Coal Consumer Council, Coal India Ltd., Kolkata

State Level Tax Advisory Committee, Govt. of Rajasthan, Jaipur

State Level Industrial Advisory Committee, Govt. of Rajasthan, Jaipur

Regional Advisory Committee, Central Excise, Jaipur

Foreign Trade Advisory Committee, Public Grievance Committee, Customs, Jaipur

DRUCC/ZRUCC of North Western Railways

केन्द्रीय कपडामंत्री एवं फूड प्रोसेसिंग राज्यमंत्री के साथ सम्पर्क बैठक

1 जून 2016 को मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की ओर से आर सी व्यास स्थित शगुन बेन्कट्स हॉल में आयोजित भव्य समारोह में भारत सरकार के कपडामंत्री माननीय श्री संतोष कुमार जी गंगवार एवं फूड प्रोसेसिंग राज्यमंत्री माननीया साध्वी निरंजना जी ज्योति एवं झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अर्जुन मुंडा ने कपडा मंत्रालय, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय एवं केन्द्र सरकार की अन्य विभिन्न विकासमुखी योजनाओं के बारे में चर्चा की एवं उद्यमियों से फीडबैक लिया। मंत्रीगण केन्द्र सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर जिला स्तर पर सम्पर्क हेतु एक दिवसीय यात्रा पर भीलवाडा पधारे थे एवं चेम्बर के आग्रह, राज्यसभा सांसद माननीय श्री वी पी सिंह की पहल पर मेवाड चेम्बर में उद्यमियों से परिचर्चा के लिए पधारे।

इस कार्यक्रम में जिले की प्रभारी मंत्री माननीया श्रीमति अनीता जी भदेल, मुख्य सचेतक माननीय श्री कालु लाल जी गुर्जर, भीलवाडा विधायक माननीय श्री विठ्ठल शंकर जी अवस्थी, माण्डलगढ विधायक माननीय बाईसा कीर्तिकुमारी जी, आसीन्द विधायक माननीय श्री रामलाल जी गुर्जर एवं भीलवाडा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के अध्यक्ष श्री दामोदर जी अग्रवाल विशिष्ट अतिथि थे। कार्यक्रम में वस्त्रमंत्रालय के नोएडा क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक श्री वी के कोहली एवं भीलवाडा के उद्यमी एवं व्यवसायियों ने भाग लिया।

उद्यमियों को सम्बोधित करते हुए माननीय कपडामंत्री ने कहाकि टेक्सटाइल उद्योग की समस्याओं के निराकरण में अब त्वरित गति से कार्य हो रहा है। अमेण्डेड टफ जारी होने से पूर्व के सभी पेडिंग आवेदनों का निस्तारण इस वर्ष की समाप्ति के पूर्व हो जाएगा। अभी तक आरआर टफ के 21 प्रकरण एवं आर-टफ के 36 प्रकरणों का निस्तारण पिछले माह में किया गया। अमेण्डेड टफ के तहत यूआईडी नम्बर जारी करना प्रारम्भ कर दिया गया है। भीलवाडा के इन्टीग्रेटेड पावरलूम कलस्टर के लिए कनकपुरा में जमीन का निर्धारण हो गया है एवं टेक्सटाइल मंत्रालय की ओर से अब भीलवाडा के कलस्टर के विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने मेवाड चेम्बर एक सक्रिय संगठन बताया एवं कहाकि यह संगठन केवल अपने क्षेत्र की समस्याओं को ही नहीं उठाकर पूरे देश के टेक्सटाइल उद्योग की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सुझाव देता है। उन्होंने मेवाड चेम्बर के सभी सदस्यों को स्वर्ण जयन्ती वर्ष की बधाई दी।

इस अवसर पर केन्द्रीय फूड प्रोसेसिंग राज्यमंत्री माननीया साध्वी निरंजना जी ज्योति ने कहाकि भारत में पूर्व में मात्र 2 प्रतिशत फल-फ्रूट-खाद्य उत्पादन की प्रोसेसिंग होती थी, पिछले 2 वर्षों में देश में 6 मेगा फूड पार्क स्थापित होने से इसमें डेढ गुणा वृद्धि हुई है। भीलवाडा के उद्यमियों को उन्होंने मेगा फूड पार्क स्थापना के लिए आगे आने को कहा। उन्होंने बताया कि छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए पार्क के लिए भूमि की आवश्यकता 50 एकड़ से घटाकर 25 एकड़ कर दी गई है।

समारोह में झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अर्जुन जी मुंडा ने कहाकि देश में आन्तरिक रिसर्च कार्य नहीं होने से हमें टेक्नोलोजी एवं मशीनरी आयात करनी पड़ रही है। सरकार का प्रयास है कि हम देश में रिसर्च एवं डवलपमेन्ट को बढ़ाकर स्वदेशी टेक्नोलोजी का विकास करें। उन्होंने उद्यमियों को आवाहन करते हुए कहाकि आज देश में चुनौतियों के मुकाबले अवसर ज्यादा है, जिसका उपयोग करके निर्यात बढ़ाने के समग्र प्रयास करने चाहिए।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में चेम्बर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री दिनेश नौलखा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि जिले से टेक्सटाइल, मिनरल एवं उत्पादों का 9 हजार करोड़ से अधिक का निर्यात किया जा रहा है। निर्यात अगले 2 वर्षों में दुगुना करने के लिए मेवाड चेम्बर की ओर से विभिन्न अन्तराष्ट्रीय संगठनों के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किए हैं। भीलवाडा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के अध्यक्ष श्री दामोदर अग्रवाल ने कहाकि पिछले 1 वर्ष में वस्त्रमंत्री की 2 बार भीलवाडा यात्रा यह संकेत देती है कि मंत्रालय की भीलवाडा के टेक्सटाइल उद्योग के विकास में गहरी रुचि है एवं समस्याओं के निराकरण के लिए कटिबद्ध है।

इससे पूर्व चेम्बर के पूर्वाध्यक्ष श्री आरएल नौलखा, श्री जेसी लढ्ढा, श्री एसएन मोदानी, डॉ पीएम बेसवाल, श्री एमडी गगरानी, उपाध्यक्ष श्री एनएन जिन्दल, श्री जेके बागडोदिया, संयुक्त सचिव श्री आरके जैन भीलवाडा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अतुल शर्मा, महासचिव श्री मुकुन सिंह, उपाध्यक्ष श्री केसी प्रहलादका एवं अन्य उद्यमियों ने पगडी, शॉल एवं माल्यार्पण से अतिथियों का स्वागत किया।

मेवाड चेम्बर के प्रतिनिधिमण्डल की वित्त राज्य मंत्री एवं वस्त्र सचिव से मुलाकात

दिनांक 25 एवं 26 मई 2016 को मेवाड चेम्बर के एक प्रतिनिधिमण्डल ने अध्यक्ष श्री अनिल मानसिंहका के साथ दिल्ली जाकर टफ योजना एवं ब्याज अनुदान तथा अन्य समस्याओं के लिए केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय श्री जयन्त जी सिन्हा एवं वस्त्र सचिव श्रीमति रश्मि वर्मा से मुलाकात की। राज्यसभा सांसद माननीय श्री वी पी सिंह जी के सक्रिय सहयोग से यह मुलाकात संभव हुई। प्रतिनिधिमण्डल में चेम्बर अध्यक्ष श्री अनिल मानसिंहका के साथ पूर्वाध्यक्ष श्री आरएल नौलखा, श्री एसएन मोदानी, डॉ पीएम बेसवाल सम्मिलित थे।

मुलाकात में वित्त राज्य मंत्री श्री जयन्त सिन्हा जी ने टफ योजना में ब्याज अनुदान में विलम्ब के मेवाड चेम्बर के प्रतिवेदन को गम्भीरता से लिया एवं वित्त सचिव एवं अन्य अधिकारियों से बात की। तदुपरान्त उन्होंने बताया कि ब्याज अनुदान के लिए इस वर्ष बजट में प्रावधानित 1500 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जाकर कपडा मंत्रालय को भिजवाई जा रही है, जिससे टफ ब्याज अनुदान एवं अन्य योजनाओं का भुगतान जून माह में कर दिया जाएगा। बकाया ब्याज अनुदान के लिए वस्त्र मंत्रालय संसद के मानसून सत्र में पूरक बजट पारित करवाने का प्रयास करेगा।

उल्लेखनीय है कि टफ योजना में ब्याज अनुदान दिसम्बर 2014 क्वाटर से लम्बित चल रहा है एवं लगभग 2 वर्ष से ब्याज अनुदान जारी नहीं होने से टेक्सटाइल इकाईयां गम्भीर संकट का सामना कर रही हैं। इसको लेकर मेवाड चेम्बर के कार्यकारणी समिति की 18 मई 2016 को आयोजित बैठक में वरिष्ठ सदस्यों का एक प्रतिनिधिमण्डल दिल्ली जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रतिनिधिमण्डल ने वस्त्र सचिव श्रीमति रश्मि वर्मा से भी मुलाकात कर उन्हें टफ योजना में यूआईडी नम्बर जारी नहीं होने एवं निर्यातकों को नवम्बर 2015 से निर्यात ऋण पर 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान की राशि प्राप्त नहीं होने की समस्या से अवगत कराया। वस्त्र सचिव ने इन दोनों समस्याओं को चालू माह के अन्त तक निवारण करने का आश्वासन दिया।

मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के सभी सदस्यों की ओर से दोनों मुलाकातों के लिए एवं प्रतिनिधिमण्डल के साथ पूरा दिन लगाकर मंत्रालयों में सम्पर्क के लिए राज्यसभा सांसद माननीय श्री वीपी सिंह जी के प्रति हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता।

मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, भीलवाडा कार्यकारणी समिति की बैठक दिनांक 18-05-2016

मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की वार्षिक आमसभा दिनांक 18.05.2016 को मेवाड चेम्बर भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष श्री अनिल मानसिंहका ने की।

1 मानद महासचिव श्री एस पी नाथानी ने बताया कि गत बैठक दिनांक 20.02.2016 को आयोजित हुई थी। इसका कार्यवाही विवरण फरवरी 2016 की पत्रिका में प्रकाशित करके सभी को प्रेषित किया गया है। आमसभा के बाद आयोजित इस बैठक में पदाधिकारियों का चुनाव किया गया था। उपस्थित सदस्यों ने दिनांक 20.02.2016 की बैठक की कार्यवाही विवरण की पुष्टि की।

निम्न सदस्यों ने अनुपस्थिति चाही जो स्वीकृत की गई –

श्री वी के हमीरवासिया	बिरला सीमेन्ट वर्क्स
श्री प्रवीण जैन	हिन्दुस्तान ज़िंक लिमिटेड
श्री वी के सोडानी	संगम इण्डिया लिमिटेड (प्रोसेस डिविजन)
श्री एन एन जिन्दल	जिन्दल मार्बल प्रा लि
श्री आर पी अग्रवाल	एसआर टेक्सफेब प्रा लि
श्री आर के जैन	आईसीएसआई भीलवाडा चेप्टर
श्री पी एस तलेसरा	तलेसरा इलेक्ट्रॉनिक्स
श्री सन्मति जैन	श्री गुड्स केरियर्स
श्री मुकेश अग्रवाल	सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स
श्री अतुल सोमाणी	ए के सोमाणी एण्ड एसोसियेट्स

चेम्बर की विभिन्न उपसमितियों का पुर्नगठन :

मानद महासचिव श्री एस पी नाथानी ने बताया कि उपसमितियों के पुर्नगठन के लिए नाम मांगे गये थे। कई सदस्यों से नाम प्राप्त हुए एवं गत बैठकों में उपस्थिति के आधार पर उपसमितियों की रुपरेखा बनाई गई है। उनके नामों की घोषणा एवं सदस्यों के आपसी विचार विमर्श एवं सुझावों के बाद विभिन्न उपसमितियों का निम्नानुसार पुर्नगठन किया गया।

मानद महासचिव श्री एस पी नाथानी ने बताया कि पूर्व में प्राप्त हुए सुझाव के अनुसार अगर किसी समिति में पूर्वाध्यक्ष है तो उन्हें समिति का चेयरमैन बनाया गया है। कार्यकारी समिति द्वारा पारित विभिन्न उपसमितियों की सूची कार्यवाही विवरण के अन्त में संलग्न है।

- 4 स्वर्ण जयन्ती समारोह के बारे में चर्चा करते हुए अध्यक्ष श्री अनिल मानसिंहका एवं मानद महासचिव श्री सूर्य प्रकाश नाथानी ने बताया कि स्वर्ण जयन्ती समारोह 27 अगस्त 2016 को आयोजित करने का तय किया गया है। इसके लिए मुख्य अतिथि के रूप में माननीया मुख्यमंत्री को, विशिष्ट अतिथियों के रूप में राज्य के उद्योगमंत्री, केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री, वस्त्र सचिव, उद्यमी श्री अनिल अग्रवाल, श्री अशोक पाटनी, श्री रघुपति सिंघानिया आदि को आमंत्रित किया जा रहा है, इनमें से कई से व्यक्तिगत मुलाकात भी की गई है। साथ ही सांसद श्री वी पी सिंह जी, श्री सुभाष जी बहेडिया, विधायक श्री वी एस अवस्थी को भी आमंत्रित करने के साथ उनके मार्फत माननीया मुख्यमंत्री एवं अन्य विशिष्ट जनों को आमंत्रित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। कार्यक्रम पूरे दिन में तीन सत्रों में होगा, रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। 50 वर्षों के क्रियाकलापों का स्मारिका प्रकाशित की जाएगी आदि।

5 नये सदस्यता प्रस्ताव :-

मानद महासचिव ने निम्न नये सदस्यता प्रस्ताव कार्यकारी समिति के सामने रखे। कार्यकारी समिति ने सर्वसम्मति से निम्न नये सदस्यता प्रस्ताव स्वीकार किये -

क्र. सं.	श्रेणी	सदस्य नाम	प्रतिनिधि का नाम
1	एसोसियेट्स	कॉरपोरेट फैशन प्रा लि	श्री विजयपाल सिंह
2	एसोसियेट्स	मिन्नोवेशन कॉर्प प्रा लि	श्री अतुल कुमार बाल्दी
3	एसोसियेशन	राजस्थान निवार मैन्यूफैक्चरिंग एसोसियेशन	श्री ओम प्रकाश गट्टाणी
4	एसोसियेट्स	गणेश फाइबर	श्री मनोज शर्मा
5	एसोसियेट्स	इण्डियानो टेलर्ड फेब्रिक्स प्रा लि	श्री पुनित सिंह
6	एसोसियेट्स	मनोमय टेक्स इण्डिया प्रा लि	श्री योगेश लड्डा

6 31 मार्च 2016 तक सदस्यता शुल्क प्राप्त नही होने से निरस्त सदस्यताओं का अनुमोदन :-

मानद महासचिव ने बताया कि निम्न सदस्यों से वर्ष 2015-16 के लिए सदस्यता शुल्क का भुगतान 31 मार्च 2016 तक प्राप्त नही होने से उक्त सदस्यताएं, नियमानुसार स्वतः निरस्त हो गई है। उन्होंने इनका विवरण कार्यकारी समिति के सामने अनुमोदन के लिए रखा।

क्र.सं.	श्रेणी	सदस्य नाम	प्रतिनिधि का नाम
1	एसोसियेट्स	अब्बाकस कोम्बीनेस प्रा लि	श्री आर जी बेरीवाल
2	एसोसियेट्स	ऐजीजु इण्डस्ट्रीयल सोल्युशन	श्री आबिद हुसैन छीपा
3	एसोसियेट्स	अजमेरी ट्यूर एण्ड ट्रावेल्स	श्री सरफराज हुसैन
4	एसोसियेट्स	जय सिन्कोटेक्स प्रा लि	श्री गिरीराज अजमेरा
5	एसोसियेट्स	कल्याण एल्युमिनियम प्रा लि	श्री सुनील डाड
6	एसोसियेट्स	लक्ष्मीलाल रामरतन	श्री मनोज जागेटिया
7	एसोसियेट्स	रॉयल सुटिंग्स प्रा.लि.	श्री आर पी जैन
8	एसोसियेट्स	एस एस इम्पेक्स	श्री विवेक बेरीवाल
9	एसोसियेट्स	साई बाबा एक्सपोर्ट इण्डिया	श्री राजीव अग्रवाल

क्र.सं.	श्रेणी	सदस्य नाम	प्रतिनिधि का नाम
10	एसोसियेट्स	सुमाटेक्स लि	श्री सुरभित मालू
11	एसोसियेशन	भीलवाडा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन	श्री प्रेम स्वरूप गर्ग
12	साधारण	चित्तौडगढ प्रोपर्टीज प्रा लि	श्री शशी झंवर
13	साधारण	गोयल होम्यो फार्मा	डॉ. भास्कर गोयल
14	साधारण	श्री महावीर कम्यूनिकेशन	श्री महावीर पिछोलिया
15	साधारण	शंकर इण्डस्ट्रीज	श्री रामावतार अग्रवाल
16	साधारण	शिवम कलेक्शन	श्री चन्द्रेश असावा
निम्न सदस्यों से त्याग पत्र प्राप्त हुए			
17	साधारण	कीर्ति टाइल्स प्रा लि	श्री राकेश माहेश्वरी
18	एसोसियेट्स	सिद्धार्थ एक्सपोर्ट	श्री मनोज मानसिंहका
19	साधारण	खाटुश्री यार्न	श्री आर के मोदी

श्री दिनेश नौलखा ने कल्याण एल्युमिनियम प्रा लि एवं शंकर इण्डस्ट्रीज तथा श्री कैलाश प्रहलादका ने रॉयल सुटिंग्स प्रा.लि. एवं भीलवाडा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन की सदस्यता तत्काल निरस्त नहीं कर उन्हें प्रयास करने का अवसर देने का अनुरोध किया, जिसे तदनुसार स्वीकार किया गया। अन्य सभी तथा त्यागपत्र प्राप्त हुए सदस्यों की सदस्यता निरस्त करने का अनुमोदन किया गया।

7 अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से –

श्री दिनेश नौलखा, डॉ पी एम बेसवाल ने टफ योजना में ब्याज अनुदान प्राप्त होने में विलम्ब एवं यूआईडी नम्बर जारी होने आदि की समस्याओं का जिक्र किया। चर्चा कर चेम्बर का एक प्रतिनिधिमण्डल अध्यक्ष श्री अनिल मानसिंहका के साथ दिल्ली जाने एवं माननीय सांसद श्री वी पी सिंह जी के सहयोग से वस्त्र मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय में मिलने का निर्णय किया गया। अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(सूर्य प्रकाश नाथानी)
मानद महासचिव

कार्यकारणी समिति की दिनांक 18.05.2016 को उपस्थित सदस्यों की सूची निम्नानुसार है –

- | | | |
|----|---|-----------------------------------|
| 1 | श्री अनिल मानसिंहका | शारदा स्पनटेक्स प्रा लि |
| 2 | डॉ पी एम बेसवाल | रंजन सुटिंग प्रा लि |
| 3 | श्री एस पी नाथानी | नाथानी फार्म |
| 4 | श्री दिनेश नौलखा | नितिन स्पिनर्स लिमिटेड |
| 5 | श्री दीपक अग्रवाल | एमआर विविंग मिल्स लिमिटेड |
| 6 | श्री एस एल पोखरना | राजस्थान कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन |
| 7 | श्री के के मोदी | मोडटेक्स टेक्सटराइजर्स प्रा लि |
| 8 | श्री कैलाश प्रहलादका | भीलवाडा टेक्सटाइल एजेंट एसोसियेशन |
| 9 | श्री प्रकाश माहेश्वरी (श्री पवन गुप्ता) | आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड गुलाबपुरा |
| 10 | श्री एम एस राठी | जया एजेन्सीज |
| 11 | श्री रामगोपाल अग्रवाल | फर्नीचर हाउस |
| 12 | डॉ अशोक सिंघल | |
| 13 | श्री वी के मानसिंहका | |

कार्यकारणी समिति की दिनांक 18.05.2016 की बैठक में वर्ष 2016-17 के लिए गठित उपसमितियां-

क्र.सं.	लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई)	सलाहकार समिति	मोबाइल	ईमेल
1	श्री के के मोदी	चेयरमेन	मोडटेक्स टेक्सटाइलजर्स प्रा लि	98290-46497 kamal_modtex@yahoo.co.in
2	श्री सरण खेमका	सदस्य	अचिंत केमीकल्स	98290-46036 achintchemicals@gmail.com
3	श्री आर पी बल्दवा	सदस्य	भीलवाडा पोलिस्टर प्रा लि	98290-46664 bhl.poly@gmail.com
4	श्री डी एल सोमाणी	सदस्य	बनवारी ग्रामोद्योग संस्थान	94141-11471 sales@washwell.in
5	श्री श्याम कुमार डाड	सदस्य	क्विक सर्विसेज	94143-72039 shyamdad@bsnl.in
6	श्री एन के जिन्दल	सदस्य	आरती सुटिंग प्रा लि	94133-56178 aartisuitings@gmail.com
7	श्री पुष्पेन्द्र बेसवाल	सदस्य	सुरज सिन्थेटिक्स प्रा लि	94141-12633 pbeswal@hotmail.com
8	श्री के एस सेठिया	सदस्य	जैन बसन्त स्पीनर्स	94141-48474 kiran.s.sethia@gmail.com
9	श्री श्याम लाल अग्रवाल	सदस्य	किराणा व्यापार मण्डल, चित्तोडगढ़	96022-30165 amit@chittorgarhoilmill.com
10	श्री एस एल लद्दा	सदस्य	श्री रिद्धी सिद्धी यार्न प्रा लि	93513-68401 slladdha@gmail.com
वृहत उद्योग सलाहकार समिति				
1	श्री आर पी सोनी	चेयरमेन	संगम ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज	98290-45411 rpsoni@sangamgroup.com
2	श्री आर एल नौलखा	सदस्य	नितिन स्पिनर्स लि	98281-48222 rln@nitinspinners.com
3	श्री राजेन्द्र गौड	सदस्य	जिन्दल शॉ लिमिटेड	77270-09276 rajender.gaur@jindalsaw.com
4	श्री प्रकाश माहेश्वरी	सदस्य	आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड	94141-66645 prakash.maheshwari@lnjbhilwara.com
5	श्री पवन गुप्ता	सदस्य	आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड	94141-13607 pawangupta@lnjbhilwara.com
6	श्री जे सी सोनी	सदस्य	बीएसएल लि	93510-06222 jcseni@bslsuitings.com
7	श्री एम एल गोयल	सदस्य	जे के सिमेन्ट वर्क्स, निम्बाहेडा	98292-46809 ml.goyal@jkcement.com
8	श्री वी के हमीरवासिया	सदस्य	बिड़ला कॉरपोरेशन लि	94141-09401 vkh@birlacement.com
9	श्री एल पी श्रीवास्तव	सदस्य	जे के टायर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि	97999-99946 lps@ktp.jkmail.com
10	श्री विमल सोनी	सदस्य	आदित्य सिमेन्ट	98874-80006 vimal.soni@adityabirla.com
11	श्री दुर्गेश बांगड	सदस्य	कंचन इण्डिया लिमिटेड	93512-10777 kanchanbhl@rediffmail.com
प्रोसेस हाउस सलाहकार समिति				
1	श्री वी के सोडानी	चेयरमेन	संगम इण्डिया लि	98290-45433 vksodani@sangamgroup.com
2	श्री सचिन राठी	सदस्य	पुजा स्पिनटेक्स प्रा लि	98290-45533 pujaspintex@gmail.com
3	श्री आर एन मित्राल	सदस्य	जानकी कॉर्प लि	94141-15957 jankicorp@yahoo.co.in
4	श्री आर एल काबरा	सदस्य	रोलेक्स प्रोसेसर्स प्रा लि	93517-11102 wiprobl@rediffmail.com
5	श्री मोहित भीमसरिया	सदस्य	रंजन पोलिस्टर्स लि	94133-56095 ranjanpoly@gmail.com
6	श्री ए के मेहता	सदस्य	बीएसएल लिमिटेड (प्रोसेर्स डिविजन)	93521-11222 akmehta@bslsuitings.com
7	श्री दुर्गेश बांगड	सदस्य	कंचन इण्डिया लिमिटेड	93512-10777 kanchanbhl@rediffmail.com
8	श्री अनिल सोनी	सदस्य	अन्नत सिनटेक्स लि	98290-46756 anantsyntexlimited@gmail.com
9	श्री एस के सुराना	सदस्य	सोना प्रोसेस (इण्डिया) लिमिटेड	98290-46277 sonaprocess@gmail.com
10	श्री के सी बाहेती	सदस्य	रोनक प्रोसेसर्स प्रा लिमिटेड	94141-11847 ronakprocessorsptltd@gmail.com
विविंग मिल्स सलाहकार समिति				
1	डॉ पी एम बेसवाल	चेयरमेन	रंजन सूटिंग्स प्रा लि	98290-45427 pmbeswal@gmail.com
2	श्री एस एल पानगड़िया	सदस्य	शुभलक्ष्मी सिन्टेक्स लिमिटेड	94141-15571 sugamfab@rediffmail.com
3	श्री संजय पेडीवाल	सदस्य	अध्यक्ष, सिन्थेटिक विविंग मिल्स एसो.	98290-45566 swmabhilwara@gmail.com
4	श्री अतुल शर्मा	सदस्य	कलर्स सलजर प्रा लि	94141-11640 caankitsharma@yahoo.com
5	श्री एन के झंवर	सदस्य	सनसिटी टेक्सटाइल प्रा लि	98290-45247 suncitytex@gmail.com
6	श्री एन के जिंदल	सदस्य	आरती सुटिंग प्रा लि	94133-56178 aartisuitings@gmail.com
7	श्री डी एम भडकतिया	सदस्य	जेन्टलमेन सुटिंग प्रा लि	98290-45591 gentlemanplus1@yahoo.com
8	श्री मो. साबिर खान	सदस्य	स्वराज सलज प्रा लि	94141-12677 swarajsuiting@gmail.com
9	श्री ललित बाबेल	सदस्य	जेपीएल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	94133-56222 jpl_ind@hotmail.com
10	श्री सुदीप गलुण्डिया	सदस्य	गलुण्डिया टेक्सटाइल प्रा लि	98290-52423 gtplgrace@gmail.com
11	श्री नरेश बाल्दी	सदस्य	नव्या फैशन प्रा लि	94133-56368 baldinaresh@yahoo.in
12	श्री एस एन इनानी	सदस्य	सत्यम सिन्कोटेक्स प्रा लि	98290-46843 satyamsyncotex@gmail.com
13	श्री दीपक अग्रवाल	सदस्य	एम आर विविंग मिल्स प्रा लि	98290-67400 deepak@babacollection.com
रेलवे एवं लोजिस्टिक सलाहकार समिति				
1	श्री वी के मानसिंगका	चेयरमेन		94141-12123 mansingkav@yahoo.com
2	श्री राजेन्द्र गौड	सदस्य	जिन्दल शॉ लिमिटेड	77270-09276 rajender.gaur@jindalsaw.com
3	श्री अशोक कुमार बाहेती	सदस्य	शुभम मिनकेम प्रा लि	94133-56347 shubcoal@bsnl.in
4	श्री सुरेश कुमार शर्मा	सदस्य	रिद्धी सिद्धी इकोलोजिस्टिक प्रा लि	98292-72668 suresh@riddhisiddhiecolistics.com
5	श्री सनमति जैन	सदस्य	श्री गुड्स केरियर्स	94141-14716 scplbhlwara@gmail.com
6	श्री डी अम्बरदार	सदस्य	ए इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	93144-97199 ambardar@kanoria.org
7	श्री प्रदीप जवेरी	सदस्य		94141-11357 shreejibaba@yahoo.co.in
8	श्री नन्दलाल नराणीवाल	सदस्य	चारभुजा इस्पात इण्डिया प्रा लि	94141-11607 charbhuja7@gmail.com
9	श्री सुभाष चुग	सदस्य	भीलवाडा पेट्रोलियम डिलर्स एसोसियेशन	94141-14688 subhash.chugh13@gmail.com
10	श्री एस एस मेहता	सदस्य	न्यूटेक रिफ्रेक्ट्रीज प्रा लि	98290-46020 nutechrefractories@yahoo.com

कार्मिक विषयक एवं विधिक सलाहकार समिति				
1	श्री आर एस सोझानी	चेयरमेन		94141-11494 sodanirs@gmail.com
2	श्री जे पी पाटोदिया	सदस्य		94130-52784 jppatodia@yahoo.com
3	श्री पी के छाजेड़	सदस्य	संगम ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज	98290-39308 pkchhajer@sangamgroup.com
4	श्री एस के जैन	सदस्य	संगम ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज	98291-53981 surendra.jain@sangamuniversity.ac.in
5	श्री एच पी माथुर	सदस्य	बीएसएल लिमिटेड	93520-45203 gen@bslsuitings.com
6	श्री के एल पारीक	सदस्य	नितिन स्पिनर्स लिमिटेड	98285-48023 klpareek@nitinspinners.com
7	श्री राजेन्द्र गौड़	सदस्य	जिन्दल शॉ लिमिटेड	77270-09276 rajender.gaur@jindalsaw.com
8	श्री पवन गुप्ता	सदस्य	आरएसइल्यूम लिमिटेड, गुलाबपुरा	94141-13607 pawangupta@lnjbhilwara.com
9	श्री महेन्द्र सिंह चौहान	सदस्य	महेन्द्र सिंह चौहान एण्ड एसोसियेट	94141-59069 rajchauhanadv@rediffmail.com
10	श्री डी अम्बरदार	सदस्य	ए इन्फ्रास्ट्रक्चर लि	93144-97199 ambardar@kanoria.org
11	श्री एस सी पानिग्रही	सदस्य	यूएमडीएस	90019-90061 sc.panigrahi@golchagroup.com
12	श्री एस के गुप्ता	सदस्य	जे के सीमेन्ट निम्बाहेडा	94141-09930 sk.gupta@jkcement.com
13	श्री बी एल नन्दवाना	सदस्य		99820-40479
14	श्री अनिल चौखडा	सदस्य	रीको ग्रोथ सेन्टर उद्योग संस्था	78914-90000 rgc_us@yahoo.com
ऊर्जा (विद्युत, कोल, गैस) सलाहकार समिति				
1	श्री अनिल मानसिंहका	चेयरमेन	शारदा स्पनटेक्स प्रा लि	98290-46101 anil@shardagroup.net
2	श्री एस के सुराना	सहचेयरमेन	सोना प्रोसेसर्स (इण्डिया) लिमिटेड	98290-46277 sonaprocess@gmail.com
3	श्री मनोज गर्ग	सदस्य	बी एस एल लिमिटेड	93517-75485 manojgarg@bslsuitings.com
4	श्री मुकेश पगारिया	सदस्य	टीपीएल इण्डस्ट्रीज लि	76654-36375 tlpbhlwara@gmail.com
5	श्री सचिन राठी	सदस्य	पुजा स्पिनटेक्स प्रा लि	98290-45533 pujaspintex@gmail.com
6	श्री अनुप सोमानी	सदस्य	संगम इण्डिया लिमिटेड	94141-14420 anoopsomani@sangamgroup.com
7	श्री एस के चौधरी	सदस्य	बिरला कॉरपोरेशन लि	9462-407377 skc@birlacement.com
8	श्री नितिन नौलखा	सदस्य	नितिन स्पिनर्स लिमिटेड	98281-48333 nitin@nitinspinners.com
9	श्री एस के लोढा	सदस्य	डायनामिक एल्कपावर प्रा लि	94141-15151 skl.dynamic@gmail.com
10	श्री एन के बहेडिया	सदस्य	आरएसइल्यूम लिमिटेड, बांसवाडा	94141-68323 nkbahedia@lnjbhilwara.com
11	श्री अशोक बाहेती	सदस्य	शुभम मिनकेम प्रा लि	94133-56347 shubcoal@bsnl.in
12	श्री संजय पेडीवाल	सदस्य	सिन्थेटिक विविंग मिल्स एसोसियेशन	98290-45566 swmabhlwara@gmail.com
13	श्री आर पी गोविल	सदस्य	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, आगूंचा	90012-94940 rp.govil@vedanta.co.in
14	श्री राजेन्द्र गौड़	सदस्य	जिन्दल शॉ लिमिटेड	77270-09276 rajender.gaur@jindalsaw.com
15	श्री जे पी गदिया	सदस्य	रीको ग्रोथ सेन्टर उद्योग संस्था	98291-09554 rgc_us@yahoo.com
16	श्री डी अम्बरदार	सदस्य	ए इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	93144-97199 ambardar@kanoria.org
आयात-निर्यात सलाहकार समिति				
1	श्री एस एन मोदानी	चेयरमेन	संगम इण्डिया लि	98290-45422 snmodani@sangamgroup.com
2	श्री दिनेश नौलखा	सदस्य	नितिन स्पिनर्स लि	98281-48111 dinesh@nitinspinners.com
3	श्री एम सी माहेश्वरी	सदस्य	बीएसएल लिमिटेड	94141-15901 mcmaheshwari@bslsuitings.com
4	श्री रंजन बेसवाल	सदस्य	रंजन सूटिंग्स प्रा लि	96606-12612 ranjanbeswal@yahoo.com
5	श्री रामसहाय जागेटिया	सदस्य	शारदा स्पूनटेक्स प्रा लि	93149-45821 info@shardagroup.net
6	श्री आर पी अग्रवाल	सदस्य	एसआर टेक्सफेब प्रा लि	94141-10802 rpagarwal_sr@yahoo.co.in
7	श्री अशोक खैराजानी	सदस्य	डी के ट्रेकिंग इण्डिया प्रा लि	99280-76236 deekay98@gmail.com
8	श्री आर के जैन	सदस्य	आर के जैन एण्ड एसोसियेट	94141-10844 rkjainbhlwara@gmail.com
9	श्री सुदीप गलुण्डिया	सदस्य	गलुण्डिया टेक्सटाइल प्रा लि	98290-52423 gtplgrace@gmail.com
10	श्री अनिल मिश्रा	सदस्य	जे के टायर एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	97999-99914 anilmishra@ktp.jkmail.com
11	श्री दीपक मानसिंहका	सदस्य	श्री महोदव कॉटन मिल्स लिमिटेड	98290-46628 mcmltd@sancharnet.in
12	श्री के के माहेश्वरी	सदस्य	आरएसइल्यूम लिमिटेड, गुलाबपुरा	94141-13603 kk.maheshwari@lnjbhilwara.com
यार्न एवं टेक्सटाइल ट्रेड सलाहकार समिति				
1	श्री अनिल मानसिंहका	चेयरमेन	शारदा स्पनटेक्स प्रा लि	98290-46101 anil@shardagroup.net
2	श्री जे के बागडोदिया	सहचेयरमेन	मंगलम यार्न एजेन्सीज	94141-10754 myayarns@datainfosys.net
3	श्री के सी प्रहलादका	सदस्य	भीलवाडा टैक्सटाइल एजेन्ट एसो.	94141-14674 shivampahladka@gmail.com
4	श्री आर पी अग्रवाल	सदस्य	एस आर टैक्सफेब प्रा लि	94141-10802 rpagarwal_sr@yahoo.co.in
5	श्री सुरेश पोद्दार	सदस्य	पोद्दार यार्न एजेन्सीज	98290-46161 poddars@sancharnet.in
6	श्री किरण सेठिया	सदस्य	जैन बसन्त स्पिनर्स	94141-48474 kiran.s. Sethia@gmail.com
7	श्री एस एस श्रीमाल	सदस्य	सिद्धार्थ एजेन्सीज	98290-45387 s.l.shrimal@gmail.com
8	श्री आर पी रंगटा	सदस्य	टेक्सटाइल यार्न हाउस	98290-45054 roongtayarns@sancharnet.in
9	श्री कमल मोदी	सदस्य	मोडटेक्स टेक्सराइजर्स प्रा लि	98290-46497 kamal_modtex@yahoo.co.in
10	श्री के जी सोमानी	सदस्य	आर्यमेन इन्टरनेशनल एक्सपोर्ट	94140-41344 pankaj186@hotmail.com
11	श्री राजेश सोमानी	सदस्य	रामकुमार टेक्सटाइल प्रा लि	93521-15161 rkumartextile@yahoo.com
12	श्री एस एल लद्धा	सदस्य	श्री रिद्धी सिद्धी यार्न प्रा लि	93513-68401 sladdha@gmail.com

	मेजर मिनरल सलाहकार समिति			
1	श्री बसन्त मानसिंहका	चेयरमेन	ए बी इम्पेक्स	94141-15329 info@abimpex.com
2	श्री राजेन्द्र गौड	सदस्य	जिंदल शॉ लिमिटेड	77270-09276 rajender.gaur@jindalsaw.com
3	श्री प्रवीण जैन	सदस्य	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, आगुंचा	99280-47578 praveen.jain@vedanta.co.in
4	श्री एस सी पानिग्रही	सदस्य	उदयपुर मिनरल डवलपेन्ट सिंडिकेट लि	90019-90061 sc.panigrahi@golchagroup.com
5	श्री नाथुराम अग्रवाल	सदस्य	पी बी एक्जिम प्रा लि	98290-45580 matraashish@gmail.com
6	श्री अनिल कुमार दासोत	सदस्य	भीलवाडा मिनरल एण्ड ग्राइडिंग इण्ड.	94141-15557 anildasot@yahoo.com
7	श्री हेमन्त मानसिंहका	सदस्य	प्रताप कॉमर्शियल कॉरपोरेशन प्रा लि	98290-45499 hmansinghka@yahoo.com
	मार्बल एवं माइनर मिनरल सलाहकार समिति			
1	श्री एन एन जिंदल	चेयरमेन	जिंदल मार्बल प्रा लि, चित्तौडगढ़	94147-34834 jindal3456@gmail.com
2	श्री गोविन्द गदिया	सदस्य	विजय टाइल्स प्रा लि, चित्तौडगढ़	94141-09048 info@vijaytiles.com
3	श्री अर्जुन मुन्दडा	सदस्य	न्याति मुन्दडा एण्ड कम्पनी, चित्तौडगढ़	94141-11446 arjunmundra@gmail.com
4	श्री एस एन मानधाना	सदस्य	पेरेडाइज मार्बल प्रा लि, चित्तौडगढ़	94141-09001 paradisemarle@rediffmail.com
5	श्री जे के बिडला	सदस्य	मीरा मार्बल प्रा लि, चित्तौडगढ़	94141-11384 jkbirla@sancharnet.in
6	श्री विपिन लद्दा	सदस्य	प्रशान्त मार्बल प्रा लि	94133-16884 laddhavin@yaho.co.in
7	श्री सुनील धारीवाल	सदस्य	पेन क्रियेशन इण्डिया	98290-46766 pancreationsindia@yahoo.co.in
8	श्री ओम प्रकाश सोनी	सदस्य	डायमण्ड हैण्डिक्राफ्ट	94141-46633 rajomsoni@gmail.com
	आयकर एवं कम्पनी अधिनियम सलाहकार समिति			
1	श्री एस पी झंवर	चेयरमेन	कालानी एण्ड कम्पनी	94141-12367 bhl@kalanico.com
2	श्री जी पी सिंघल	सदस्य	जी पी सिंघल एण्ड कम्पनी	94141-12350 singhal81@hotmail.com
3	श्री वी एस तापडिया	सदस्य	भीलवाडा ब्रांच ऑफ आईसीएसआई	93142-35114 vstapadia@gmail.com
4	श्री के सी तातेड	सदस्य	के सी तातेड एण्ड एसोसियेट्स	98291-92198 kctater@gmail.com
5	श्री अतुल सोमानी	सदस्य	ए के सोमानी एण्ड एसोसियेट्स	98291-26375 aksomani_ca@yahoo.com
6	श्री संजय डाड	सदस्य	एस डाड एण्ड कम्पनी	98290-47880 sanjaydad@rediffmail.com
7	श्री के के माहेश्वरी	सदस्य	आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड, गुलाबपुरा	94141-13603 kk.maheshwari@lnjbhilwara.com
8	श्री राकेश चन्द्र मंत्री	सदस्य		94141-10007 rakesh.mantri786@gmail.com
9	श्री आर एस जैथलिया	सदस्य		94133-55554
10	श्री सोहनलाल कोगटा	सदस्य		94136-24501 s_kogta@rediffmail.com
11	श्री नितिन मेहता	सदस्य	नेचुरल इन्टरनेशनल ट्रेड प्रा लि	98291-05613 nitin2080@gmail.com
12	श्री वी के गोयल	सदस्य	वी के गोयल एण्ड कम्पनी	94142-93450 vkg.company@yahoo.co.in
13	श्री हरीश काकानी	सदस्य	एचकेबीएस एण्ड एसोसियेट्स	94142-60315 hkbs@rediffmail.com
	व्यापारिक एवं वाणिज्यकर सलाहकार समिति			
1	श्री रामस्वरूप जैथलिया	चेयरमेन		94133-55554
2	श्री ए के सोमानी	सहचेयरमेन	ए के सोमानी एण्ड एसोसियेट	98291-26375 aksomani_ca@yahoo.com
3	श्री वी के मानसिंगका	सदस्य		94141-12123 mansinghav@yahoo.com
4	श्री पी एस तलेसरा	सदस्य	तलेसरा इलेक्ट्रीकल्स	99293-86000 talesara_anil@yahoo.co.in
5	श्री के के माहेश्वरी	सदस्य	आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड, गुलाबपुरा	94141-13603 kk.maheshwari@lnjbhilwara.com
6	श्री पीयूष सिंघल	सदस्य	सिंघल एसोसियेट	93521-10660 singhal81@hotmail.com
7	श्री रामस्वरूप अग्रवाल	सदस्य	भीलवाडा ऑटो एण्ड मशीनरी डीलर एसो.	98282-36397
8	श्री एस एल पोखरना	सदस्य	राजस्थान कॉमर्शियल कॉरपोरेशन	98290-95543 rccbhilwara@yahoo.com
9	श्री रामगोपाल अग्रवाल	सदस्य	फर्नीचर हाउस	94141-15674 aramgopal@gmail.com
10	श्री श्याम लाल अग्रवाल	सदस्य	किराणा व्यापार मण्डल, चित्तौडगढ़	96022-30165 amit@chittorgarhoilmill.com
11	श्री सोहनलाल कोगटा	सदस्य		94136-24501 s_kogta@rediffmail.com
12	श्री अशोक काबरा	सदस्य		94142-59901 grsecurities_bhilwara@yahoo.com
13	श्री मुकेश अग्रवाल	सदस्य	सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स	92143-03225 super.telecom@gmail.com
	केन्द्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क एवं सेवाकर सलाहकार समिति			
1	श्री आर के जैन	चेयरमेन	आर के जैन एण्ड एसोसियेट्स	94141-10844 rkjainbhilwara@gmail.com
2	श्री अनिल मिश्रा	सदस्य	जे के टायर एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	97999-99914 anilmishra@ktp.jkmail.com
3	श्री जी सी जैन	सदस्य	सम्यक सिन्थेटिक्स प्रा लि	98290-47079 samyak.synthetics@gmail.com
4	श्री अनिल राठी	सदस्य	अनिल प्रहलाद राठी एण्ड कम्पनी	94133-58080 anilprathi@rediffmail.com
5	श्री वी के गोयल	सदस्य	वी के गोयल एण्ड कम्पनी	94142-93450 vkg.company@yahoo.co.in
6	श्री सुधीर गर्ग	सदस्य	नितिन स्पिनर्स लिमिटेड	98281-48018 sudhirgarg@nitinspinners.com
7	श्री जे के जैन	सदस्य	बांसवाडा सिन्टेक्स लि	94141-01844 jkjain@banswarafabrics.com
8	श्री जे पी बाबेल	सदस्य	बांसवाडा सिन्टेक्स लि	92510-14309 jpbabel@banswarafabrics.com
9	श्री प्रवीण जैन	सदस्य	बी एस एल लि.	93521-11233 praveenjain@bslsuitings.com
10	श्री आर पी अग्रवाल	सदस्य	एस आर टेक्सफेब प्रा लि	94141-10802 rpagarwal_sr@yahoo.co.in
11	श्री अशोक खैराजानी	सदस्य	डी के ट्रेकिंग इण्डिया प्रा लि	99280-76236 deekay98@gmail.com
12	श्री अर्जुन मुन्दडा	सदस्य	न्याति मुन्दडा एण्ड कम्पनी	94141-11446 arjunmundra@gmail.com

जल एवं पर्यावरण सलाहकार समिति			
1	श्री देवेन्द्र देराश्री	चेयरमेन	98291-09502 paniwale@gmail.com
2	श्री डी अम्बरदार	सदस्य ए इन्फ्रास्ट्रक्चर लि	93144-97199 ambardar@kanoria.org
3	श्री ए के मेहता	सदस्य बीएसएल लिमिटेड (प्रोसेस डिजिज)	93521-11222 akmehta@bssluitings.com
4	श्री सचिन राठी	सदस्य पूजा स्पिनटेक्स प्रा लि	98290-45533 pujaspintex@gmail.com
5	श्री प्रकाश छाबडा	सदस्य ए के स्पिनटेक्स प्रा लि	98290-46573 akspintex@gmail.com
6	श्री राजेन्द्र गौड	सदस्य जिंदल शॉ लिमिटेड	77270-09276 rajender.gaur@jindalsaw.com
7	श्री सचिन सामर	सदस्य हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, आगुचा	90012-92870 sachin.samar@vedanta.co.in
8	श्री एन एन जिंदल	सदस्य जिन्दल मार्बल प्रा लि	94147-34834 jindal3456@gmail.com
9	श्री एल पी श्रीवास्तव	सदस्य जे के टायर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि	97999-99946 lps@ktp.jkmail.com
10	श्री वी के हमीरवासिया	सदस्य बिड़ला कॉरपोरेशन लि	94141-09401 vkh@birlacement.com
11	श्री जे पी गदिया	सदस्य रीको ग्रोथ सेंटर उद्योग संस्था	98291-09554 rgc_us@yahoo.com
12	श्री विनोद कुमार मानसिंगका	सदस्य	94141-12123 mansinglav@yahoo.com
विभिन्न संस्थान में मेवाड चेम्बर की ओर से प्रतिनिधित्व के लिये नाम			
1	राजस्थान वित्त निगम	श्री आर पी बल्दवा	98290-46664 bhl.poly@gmail.com
2	रीको लिमिटेड	डॉ पी एम बेसवाल	98290-45427 ranjanbeswal@yahoo.com
3	रीको लिमिटेड	श्री जे पी गदिया	98291-09554 rgc_us@yahoo.com
4	रीको लिमिटेड	श्री राजेन्द्र गौड	77270-09276 rajender.gaur@jindalsaw.com
5	अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.	श्री एस के सुराना	98290-46277 sonaprocess@gmail.com
6	अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.	श्री राजेन्द्र गौड	77270-09276 rajender.gaur@jindalsaw.com
7	अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.	श्री एन के बहेडिया, बांसवाडा	94141-68323 nkbahedia@lnjbhilwara.com
8	रेलवे विभाग	श्री वी के मानसिंगका	94141-12123 mansinglav@yahoo.com
9	जिला उद्योग केन्द्र	श्री दीपक अग्रवाल	98290-67400 deepak@babacollection.com
10	जिला उद्योग केन्द्र	श्री राजेन्द्र गौड	77270-09276 rajender.gaur@jindalsaw.com
11	वाणिज्यकर विभाग	श्री आर एस जैथलिया	94133-55554
12	वाणिज्यकर विभाग	श्री अतुल सामाणी	98291-26375 aksomani_ca@yahoo.com
13	आयकर विभाग	श्री एस पी झंवर	94141-12367 bhl@kalanico.com
14	आयकर विभाग	श्री जी पी सिंघल	94141-12350 singhal81@hotmail.com
15	उत्पाद एवं सेवाकर	श्री आर के जैन	94141-10844 rkjainbhlwara@gmail.com
16	उत्पाद एवं सेवाकर	श्री जे पी बाबेल	92510-14309 jpbabel@banswarafabrics.com
17	श्रम विभाग	श्री आर एस सोडाणी	94141-11494 sodanirs@gmail.com
18	श्रम विभाग	श्री पवन गुप्ता	94141-13607 pawangupta@lnjbhilwara.com
19	कर्मचारी भविष्य निधि/ईएसआई	श्री अनिल चौखडा	78914-90000 rgc_us@yahoo.com
20	कर्मचारी भविष्य निधि/ईएसआई	श्री विनोद मानसिंगका	94141-12123 mansinglav@yahoo.com

सोनियाणा औद्योगिक क्षेत्र के लिए पर्यावरण स्वीकृति जारी

राजस्थान स्टेट लेवल इन्वायरमेन्ट इम्पेक्ट एसेसमेन्ट ऑथोरिटी द्वारा 6 मई 2016 को सोनियाणा तहसील गंगरार में रीको द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र की पर्यावरण स्वीकृति जारी कर दी गई है। रीको ने 21.11.2011 को इसके लिए आवेदन किया था। इस महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने में 5 वर्ष का समय लग गया। स्वीकृति के अनुसार रीको द्वारा सोनियाणा में 343.23 हेक्टर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। जिसमें से 231.92 हेक्टर में औद्योगिक भूखण्ड काटे जा सकेंगे। औद्योगिक क्षेत्र के विकास की कुल प्रोजेक्ट लागत 285.65 करोड़ बताई गई है। इस क्षेत्र में रीको द्वारा स्वयं के स्तर पर केन्द्रीय भूजल विभाग से स्वीकृति प्राप्त की जाकर बोरवेलों के जरिये पानी की व्यवस्था की जाएगी। 4 हेक्टर भूमि पर सीईपीटी की स्थापना की जाएगी।

मेगापावरलूम कलस्टर के लिए करणपुरा में भूमि आवंटन

जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार मेगापावरलूम कलस्टर के लिए राज्य सरकार द्वारा रीको को माण्डलगढ तहसील के करणपुरा गांव में 30.67 हेक्टर भूमि आवंटित की गई है। रीको द्वारा भूमि की लागत राशि जमा करा दी गई है। श्रीनाथ मेगाटेक्स प्रोसेस कलस्टर प्रा लि द्वारा यहां मेगा कलस्टर की स्थापना की जाएगी, जिसमें 50 इकाईयां प्रस्तावित हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 6 प्रोसेस हाउस, 5 यार्न डाईंग, 19 विविंग, 9 रेडीमेड गारमेन्ट एवं अन्य उद्योग स्थापित होंगे। मेगापावरलूम कलस्टर स्थापना पर 120 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

SME LISTING PLATFORM: NEW OPPORTUNITY FOR SME'S

National Stock exchange (NSE) in association with Mewar Chamber of Commerce and Industry, ICAI Bhilwara Branch and Hem Securities Limited conducted a event on “SME Listing Platform: New Opportunity for SME's” on 20th Friday, 2016. Chief guest for the event was “CA Pradeep Somani”. MCCI President Shri Anil Mansinghka was Guest of Honour. Speakers for the event included Mr. Rakesh Khurana (Dy. Manager, NSE) and Mr. Gaurav Jain (Director, Hem Securities Limited). The event was attended by prominent Industrialist and Chartered Accountants based in Bhilwara.

During their presentation and deliberations, NSE & Hem Securities Limited representatives touched upon details of Introduction to NSE SME Platform, Value for SME's/Consultants and SME Emerge Criteria & Listing Process. The experts also solved doubts of the participants with regards to the platform.

Bhilwara has huge potential in terms of expansion and growth, SME IPO Platform will provide a number of benefits to the SME's in terms of Visibility, Value creation, Brand Building, easy banking facility and Taxation benefit. Already, one company from Bhilwara i.e. Swagat Synthetics Limited (Now, Sitaram India Limited) is in process of Being listed on the exchange and there is a massive response from SME's in Bhilwara to get listed on this exchange.

Vastra 2016 – An International Textile and Apparel Fair” Mewar Chamber of Commerce & Industry-Support organization

Rajasthan Industrial Development & Investment Corporation Ltd (RIICO) and FICCI are jointly organizing the fifth edition of VASTRA i.e. “Vastra 2016 – An International Textile and Apparel Fair” during October 20-23, 2016 at Jaipur Exhibition and Convention Centre, Sitapura Industrial Area, Jaipur.

4th edition of the event- Vastra in 2015 received tremendous response from exhibitors as well as buyers. Participation of 252 exhibitors and over 300 overseas visitors from 59 countries, 4605 buyer seller meetings and business generated worth US\$69 million are some of the highlights of the show and testimony to the growing stature of the event.

Mewar Chambers of Commerce & Industry as one of the leading association in textile & apparel sector in India has been invited as **Support organization** for VASTRA 2016.

KEY INPUT SHORTAGE STRANDS POLYESTER-MAKERS

Anti-dumping duty compounds misery

Polyester producing companies have cut production by 40 per cent in last three months due to acute shortage of key raw material PTA (purified terephthalic acid) supplied by oil refining companies such as Reliance Industries and Indian Oil Corporation besides MCC PTA India which shut production in some of their units for various reasons.

MS Bagheria, Chairman, Filatex India said Reliance Industries, the largest producer of PTA had cut production between March and May for two weeks each and it is allocating only 50 per cent of demand to all its customers since April. Similarly, he added, IOC supplied only 70 per cent of its customers demand since February before taking a complete shut down in April for 15 days while MCPI took month long shut down in February and supplied less than 50 per cent of the contracted volume to each customer.

Interestingly, the polyester manufacturers require 5.3 million tonnes of PTA per annum, while the country has production capacity of 6 million tonne with Reliance Industries itself commanding annual production capacity of 3.2 million tonne. Reliance is the largest producer of polyester fibre and yarn in the world, with a capacity of 2.5 million tonnes per annum. Reliance said it has suspended PTA production at its Dahej unit due to water shortage.

Double Whammy

The anti-dumping duty of 15 per cent levied in December has made import of PTA unviable for the polyester industry, said Bagheria. Unlike other PTA users, the polyester companies, which is among the largest employment generators, cannot afford imports after the anti-dumping duty as they are operating at wafer-thin EBITDA margin of 6-7 per cent, he added.

RK Vij, General Secretary, PTA Users Association said with the domestic PTA in short supply and anti-dumping duty on imports, the polyester industry is struggling for survival with levy of \$108 a tonne on PTA import price of \$600 a tonne works out to about 18 per cent. “The industry is facing two-prong problems. On one hand, it is not getting enough domestic supply of raw material and on the other the Government has imposed anti-dumping duty on imports from Thailand, Korea, China, Iran, Indonesia, Malaysia and Taiwan,” he added. Bagheria said a steady supply of raw material is key for operating a polyester plant

as it is a continuous process and cannot be shut and restarted at once will. "To shut and restart a polyester plant with daily capacity of 200-300 tonnes would cost about Rs 1 crore.

It is high time the Government removes the anti-dumping before things go out of hand," he said. Of the annual installed polyester production capacity of 8.4 million tonnes, companies have produced only 5.8 million tonnes due to raw material shortage. Currently, Vij said industry has idled about 1000-1500 tonnes of daily production capacity due to non-availability of PTA. Highlighting the undue protection to large PTA producers, Vij said while import of PTA attracts a duty of 15-20 per cent, the government allows duty free import of paraxyle, which is raw material for producing PTA. Due to the inverted duty structure, Indian polyester products have become costlier by 15-20 per cent making exports unviable. The current situation has led to import of fabrics and yarn are going up. Last fiscal cumulative imports of polyester fibre and yarn had gone up 13 per cent to 139,909 tonnes (123,993 tonnes).

(Source: Suresh P Iyengar, Business Line, June 02, 2016)

**Shri V.P.Singh, Member Rajya Sabha participated in debate on
THE APPROPRIATION (NO.2) BILL, 2016 AND THE FINANCE BILL, 2016
Details of his speech**

MR. DEPUTY CHAIRMAN:

The Appropriation (No.2) Bill, 2016 and the Finance Bill, 2016 have already been moved. And Shri V.P. Singh Badnore was speaking yesterday. At that time, I had to adjourn the House. But, kindly note that the time allotted now is three hours only. 92 Uncorrected/ Not for Publication-11.05.2016 Therefore, every Party's time is curtailed to that extent. The Chair will be very strict regarding time. You may manage your speech within the allotted time. I will announce the time allotted to each Member before he has to start. Now, Shri V.P. Singh Badnore, you may take ten minutes. (Interruptions) Your Minister is agreeing to that.

SHRI V.P. SINGH BADNORE (RAJASTHAN): Sir, I don't waste time to repeat what I had said yesterday. But, as there was a lot of din, I think, I have to give a gist of what I had said yesterday because everybody could not hear what I was saying. Sir, I was trying to support the Finance Bill, 2016 and the Appropriation (No.2) Bill, 2016. Let me start by saying that we have the Budget pronouncement and then we have the annual Budget discussion on it. Then, we have a recess where the Ministry's demands are discussed in the Standing Committees. We have today come to the last stage of the Budget, that is, the Finance Bill. No one can deny that there was a distinct slowdown in our growth story in the last two-three years of the UPA Government, which was hovering around 6 per cent.

There were various reasons, not just external but internal as well, like scams in the 2G, 3G, Coal, Commonwealth 93 Uncorrected/ Not for Publication-11.05.2016 Games and others. But, let me, at this stage, not enumerate them. Whatsoever, instead, I need to commend our hon. Prime Minister and the Finance Minister that because of their new initiatives, we have today the fastest GDP growth in the world, which is 7.6 per cent beating China, which this year is at 6.9 per cent. In the 21st Century, no country can survive in seclusion and not be dependent, in some way or another, on other countries. Therefore, today's volatility in the global economy is a prime concern. While the world's GDP is 3.5 per cent, ours is more than double at 7.6 per cent.

(Contd. by DC/2F) -KGG/DC-ASC/2.20/2F SHRI V.P. SINGH BADNORE (CONTD.): On one count, we have been very lucky, i.e., with the oil prices, but, our monsoon had failed us and because of the rainfall being lower than the average, it impacted our agriculture and, therefore, it impacted the GDP, as well. Let me dwell on the subject of our present position in the world economy. China is the world's third largest economy behind the US and the EU, which is 28 countries together. China has 10.3 trillion US dollars, while India is still at two trillion. China slowed down to 6.9 per 94 Uncorrected/ Not for Publication-11.05.2016 cent and they have sustained 9 to 10 per cent for the last 25 years. So India's GDP, today, is the fastest at 7.6 per cent but at two trillion, we are far behind the advanced countries like China, and to keep up or get to the levels of the advanced countries, we will have to really sustain this GDP growth for a long, long time. Going down the memory lane, let us see where we faltered these many years. As everybody knows, the countries which have become advanced, they went through the second World War and coming out of the scars of the second World War, they still galloped and went away, and we were left where we are. And if we see that, from 1950s to 1980s, India had a GDP growth of only 3 to 3.5 per cent. From 1980s to 2010, we had a GDP growth of 6 to 6.5 per cent. If the GDP is over 8 to 9 per cent, then, our per capita will increase by about 7.5 per cent. That would double in 10 years and that is the arithmetic.

As I said, we learn from history and let us see where we went wrong. It is no secret that over the years, for 37 years after Independence, out of the 42 years, Congress was at the helm of affairs. It is also no secret that the economists the world over, called that regime, 'Asia's great economic flops'. In contrast, neither of the 95 Uncorrected/ Not for Publication-11.05.2016 post-1991 India's reform heroes, Shri P.V. Narasimha Rao and Shri Atal Bihar Vajpayee, belonged to the famous dynasty. That is why I call them heroes for dismantling the economic pillars of the Nehruvian era and the Soviet style planning. Famous classical liberals like B.R. Shenoy and future Nobel laureate Milton Friedman raised early alarms about India's chosen paths, but the conventional wisdom of the time went unheeded. In normal political system, Congress would have levated...(Interruptions)...

SHRI PRAMOD TIWARI: Sir, both the Finance Ministers are missing. Neither the Cabinet Minister, nor the State Minister is there. ...(Interruptions)... SHRI V.P. SINGH BADNORE: I am not bothered. Please...(Interruptions)... I am not bothered. ...(Interruptions)... MR. DEPUTY CHAIRMAN: Call the Minister of State for Finance. SHRI V.P. SINGH BADNORE: Sir, in normal political system, Congress would have elevated ..(Interruptions)... They are coming, Sir. 96 Uncorrected/ Not for Publication-11.05.2016 MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister of State for Finance should come, at least. ...(Interruptions)... Where is Shri Jayant Sinha? ...(Interruptions)... Call the Minister of State for Finance. ...(Interruptions)... THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI GHULAM NABIAZAD): Sir, this is a very important Bill. ...(Interruptions)... You toppled the Uttarakhand Government on the Uttarakhand Appropriation Bill and now we are discussing the Appropriation Bill of the entire country in the Parliament and no Minister is available. ...(Interruptions)... SHRI V.P. SINGH BADNORE: It does not bother me. ...(Interruptions)... It is not bothering me. ...(Interruptions)... (Followed by 2G/TDB) TDB-LP/2G/2.25 SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, you adjourn the House till one of them comes. ...(Interruptions)... Sir, you adjourn the House. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, okay; the MoS has come. That is okay. ...(Interruptions)... See, if the Finance Minister is not here, you should be here. ...(Interruptions)... THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA): I know, Sir. ...(Interruptions)... MR. DEPUTY CHAIRMAN: And Shri Jairam Ramesh is sitting on the other side. Be careful. ...(Interruptions)... SHRI JAYANT SINHA: Sir, only when our speaker was on his legs... ...(Interruptions)... SHRI V.P. SINGH BADNORE: In normal political system, Congress would have elevated Shri P.V. Narasimha Rao to sainthood and quietly banished the discredited first family. But they did not do so. Sadly, it seems, that the legacy of that time still exists today, and that is how we see that even in this House, they are not ready to pass the 98 Uncorrected/ Not for Publication-11.05.2016 reform Bills, the GST Bill. ...(Interruptions)... And I feel that still echoes in this House. For instance, and it is really paradoxical to see that Shri Manmohan Singh under Shri P.V. Narasimha Rao and then later in the UPA-1 and UPA-2... MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have taken nine minutes, remember. What do I do? SHRI V.P. SINGH BADNORE: Sir, let me carry on, at least. There is no comparison. ...(Interruptions)... SHRI MADHUSUDAN MISTRY: ...ruling party, therefore, they take more time. ...(Interruptions)... SHRI V.P. SINGH BADNORE: Sir, I have started it. MR. DEPUTY CHAIRMAN: What do I do? SHRI V.P. SINGH BADNORE: Sir, there is only one more speaker from our party, and he will not take much time. ...(Interruptions)... SHRI AJAY SANCHETI: Sir,... ...(Interruptions)... MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, you will withdraw. You don't speak. SHRI AJAY SANCHETI: No, Sir. ...(Interruptions)... MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; your party has told me that. 99 Uncorrected/ Not for Publication-11.05.2016 SHRI AJAY SANCHETI: There is still a lot of time. I will speak only for five minutes. ...(Interruptions)... SHRI V.P. SINGH BADNORE: Sir, he will speak for five minutes. MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your party has allotted you ten minutes. Okay, you take two, three minutes more. ...(Interruptions)...

SHRI V.P. SINGH BADNORE: Sir, it is a fact that a well-known New York University Professor William Easterly details in 'The Tyranny of Experts' and puts it, "It took decades to discredit the statist development model of Gunnar Myrdal and Arthur Lewis, Indians were not alone in suffering, millions of Africans, Latin Americans and many, kept them company." Getting back to the present times and the Budget in hand; the high point of the Budget, and I need to commend the hon. Prime Minister and the Finance Minister in adhering to the roadmap of fiscal consolidation by fixing the fiscal deficit at 3.5 per cent of the GDP; and containing the inflation. Sir, it is of significance to state that the nine pillars flagged by the Finance Minister are in the right direction to transform India. Sir, I will go fast as I wanted to explain all that. They are: Agriculture and 100 Uncorrected/ Not for Publication-11.05.2016 farmers' welfare; rural sector; healthcare; education/skills/job creation; infrastructure; financial sector reforms to bring transparency and stability; governance and ease of doing business and boost opportunities; fiscal discipline, and; tax reforms to reduce compliance burden. Sir, let me add here that the United Nations Organisation and 74 countries have endorsed the view that instead of GDP -- this is very important -- as an index of economic growth, GNH (Gross National Happiness) may be a better and richer objective and considered as a national measure. So, that should be the new measure as the UNO has agreed to it, and even 74 countries have endorsed it.

Sir, if we look at the nine pillars put forth, in this year's Budget, much stress has been put on the well-being and happiness. Be it, opportunities, farmers' welfare, ease of doing business, health insurance schemes, Atal Pension Yojana, education, targeted subsidies, MUDRA, Jan Dhan Yojana, Swachh Bharat Yojana, Startups and all that which is at the core of the GNH index. This new concept has been floated by none other than the happy and friendly Bhutanese people, who are our neighbours. 101 Uncorrected/ Not for Publication-11.05.2016 Sir, in the end, I have some suggestions for the hon. Finance Minister. The technology used in the Revenue Department needs upgradation and amendments. The new technology will make the system more transparent and fast. Right now the digital technology used by the officers of the Revenue Department seems outdated and is 10 years behind. Moreover, there should be a single, i.e., only one website for all Income Tax Department-related websites. Presently, it is www.tdscpc.gov.in for filing of TDS returns and other transactions related to TDS.

(Contd. by 2H-USY) USY/2H/2.30 SHRI V.P. SINGH BADNORE (CONTD.): And, there is another one www.tin-nsdl.com for getting/ issuing new PAN/TAN cards. There should be only one website. Therefore, I suggest that all these websites should be merged and integrated into a single website, which would handle the whole Income Tax Department in a better way. MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes; yes. I am not stopping you. 102 Uncorrected/ Not for Publication-11.05.2016 SHRI V.P. SINGH BADNORE: Some litigations crop up due to law drafting interpretations. The CBDT should be directed to issue timely clarifications with suitable examples to make it clear. This would lessen disputes arising regarding interpretations. More accountability of the Government employees needs to be fixed so that disposal is made time-bound and litigation is minimized. By early disposal of appeals and references, repetitive additions can be avoided, which result into unnecessary harassment to general public and creation of outstanding tax demands.

There is an issue of tax deducted at source (TDS) compliance and filing of quarterly returns, issue of form 16A for each quarter. There are issues in systems for chalan/PAN matching, which need to be streamlined. Sixty per cent of the problems are because of mismatched bank information and IT records. Presently, a large number of old demands are being created because of mismatched bank information and IT records, on account of digitalization of all income tax records. Lastly, the CPC at Bangalore needs to be equipped with professionals. They need to reply and rectify the queries. When a 103 Uncorrected/ Not for Publication-11.05.2016 query comes, it needs to be filtered and errors and mistakes need to be corrected, identified and solutions should be given by the CPC. But this is not being done as they are not manned by skilled professionals. With these words, I support the Finance Bill, 2016 and the Appropriation Bill.

Thank you.

KRISHI KALYAN CESS – APPLICABILITY & OPEN ISSUES

Pursuing with an objective to finance and promote initiatives to improve agriculture and farmer welfare, the Government announced a new cess namely 'KrishiKalyan Cess' (“KKC”), to be levied at 0.5% on the value of all taxable services w.e.f June 1, 2016. In this regard, a new Chapter VI was inserted in the Finance Bill, 2016, containing relevant provisions, which are applicable with enactment of the Finance Act, 2016 on May 14, 2016.

Hence, after levy of KKC, Service tax rate will increase from 14.5% to 15%, effective from June 1, 2016. An illustration showing levy of Service tax and Swachh Bharat Cess (“SB Cess”) & KKC is given below assuming Rs. 1,000/- as value of a taxable service:

Particulars	Tax/ Cess (Rs.)
Value of taxable service: (a)	1,000/-
Add: Service tax @ 14% on (a)	140/-
Add: SB Cess @ 0.5% on (a)	5/-
Add: KKC @ 0.5% on (a)	5/-
Total:	1,150/-

The Central Government vide **Circular No. 194/4/2016-ST dated May 26, 2016** has notified accounting codes for payment of KKC in the following manner:

KKC (Minor Head)	Tax Collection	Other Reciepts (Interest)	Deduct Refunds	Penalties
0044-00-507	00441509	00441510	00441511	00441512

Now, the Central Government has issued following Notifications to clarify on calculation of value of taxable services under Reverse Charge Notification/ Abatement Notification/ Valuation Rules, Rebate of KKC on input services used for provision of export of services, Refund of KKC paid on specified services used in SEZ, calculation of Alternate rate of Service tax in specified cases, availability of Cenvat credit of KKC etc.:

A. Clarifications on various aspects of KKC

KKC along with Service tax & SB Cess shall be paid on Services under Reverse Charge Mechanism– Notification No. 27/2016-ST dated May 26, 2016:

The Reverse Charge Notification No. 30/2012-ST dated June 20, 2012 (“**Reverse Charge Notification**”) prescribes the specified services under full reverse charge wherein 100% Service tax to be paid by the Service Recipient and under partial reverse charge wherein both the Service Provider and Service Recipient has to pay specified percentage of Service tax.

Now, the Central Government vide Notification No. 27/2016-ST dated May 26, 2016, has amended/clarified that the Reverse Charge Notification shall be applicable mutatis mutandis for the purposes of KKC also. In other words, KKC along with Service tax shall be paid on taxable services under Reverse Charge and Partial Reverse Charge Mechanism as well.

Notification No. 28/2016-ST dated May 26, 2016 (“Notification No. 28”):

No KKC on services specified under the Negative List of services or otherwise exempted by a Notification/ Special Order issued under Section 93(1)/ Section 93(2) respectively of the Finance Act, 1994

The Central Government vide Notification No. 28 has provided that KKC shall not be leviable on services which are exempt from Service tax by a Notification issued under Section 93(1) or Special Order issued under Section 93(2) of the Finance Act, 1994 (“**the Finance Act**”) or otherwise not leviable to Service tax under Section 66B thereof. Therefore, KKC @ 0.5% will be levied on value of all taxable services except the following:

- ☐ Activity excluded from the definition of Service under Section 65B(44) of the Finance Act;
- ☐ Negative List of Services under Section 66D of the Finance Act;
- ☐ Services exempted by a notification issued under Section 93(1) of the Finance Act i.e.
- ☐ Services exempted under Mega Exemption Notification vide Notification No. 25/2012-ST dated June 20, 2012.
- ☐ Services exempted, as specified to specified percentage under the Abatement Notification No. 26/2012-ST dated June 20, 2012;
- ☐ Services exempted by Special Order issued under Section 93(2) of the Finance Act

KKC@ 0.5% will be levied on value of all taxable services after availing abatement:

Notification No. 28 further clarifies that KKC will be levied on value of taxable services after availing the benefit of abatements by way of an exemption provided vide Abatement Notification No. 26/2012-ST dated June 20, 2012 i.e. KKC would be computed on abated value of taxable services.

For example, in case of GTA services (other than used household goods), presently, abatement of 70% is available and accordingly, Service tax is required to be paid on 30% of value of taxable service after exemption (abatement) of 70% as provided under the said Abatement Notification. The effective rate of Service tax including SB Cess and KKC would be 4.50% (i.e. 30% of 15%).

Value of taxable services for the purposes of KKC shall be the value as determined in accordance with the Service Tax (Determination of Value) Rules, 2006 (“the Service Tax Valuation Rules”):

Notification No. 28 furthermore clarifies that value of taxable services for the purposes of KKC shall be the value as determined in accordance with the Service Tax Valuation Rules. Thus, KKC would be levied in the following manner:

- a. Computation of tax under Works contract: In terms of Rule 2A of the Service Tax Valuation Rules, Service tax along with SB Cess and KKC needs to be applied on taxable value. Accordingly, effective rate of Service tax would be as under:
In case of original works: 6% (15%*40%); and
Other than original works: 10.50% (15%*70%)
- b. Computation of tax on Restaurant and Outdoor catering services: In terms of Rule 2C of the Service Tax Valuation Rules, Service tax along with SB Cess and KKC needs to be applied on taxable value. Accordingly, effective rate of Service tax would be as under:
In case of AC Restaurant services: 6% (15%*40%); and
In case of Outdoor catering services: 9% (15%*60%)

Rebate of KKC paid on input services used for provision of export of services -Notification No. 29/ 2016-ST dated May 26, 2016:

The Central Government vide Notification No. 29/2016-ST dated May 26, 2016, has amended Notification No. 39/2012-ST dated June 20, 2012 (Rebate of the duty paid on excisable inputs or Service tax and cess paid on all input services used in providing service exported) to insert KKC under the definition of “service tax and cess”, to enable the provider of services to claim rebate of KKC paid on all the input services used in providing services exported in terms of Rule 6A of the Service Tax Rules, 1994.

Amendment in the Service Tax Rules, 1994 for providing alternate rate for KKC– Notification No. 31/2016-ST dated May 26, 2016:

As per sub-rules 7, 7A, 7B and 7C to Rule 6 of the Service Tax Rules, 1994 (“**the Service Tax Rules**”), there is an alternative rate of Service tax for services, namely, air travel agents, insurance premium, purchase & sale of foreign currency and lottery distributor.

The Central Government vide Notification No. 31/2016-ST dated May 26, 2016 has amended the Service Tax Rules to insert sub-rule (7E) after sub-rule (7D), which prescribes that if Service tax is payable at an alternative rate, KKC would also be computed in proportion to such alternative rate, in similar manner as it was prescribed at the time of introduction of SB Cess:

Total Service tax liability calculated under Rule 6(7), (7A), (7B) or (7C) * 0.5

For example, in case of air travel agent services, air travel agent opting alternative rate of Service tax is liable to pay Service tax at the rate of 0.7% of the basic fare in case of domestic bookings and at the rate of 1.4% of the basic fare in the case of international bookings. Therefore, KKC would be payable at the following rates:

Domestic bookings: $0.7\% \times 0.5\% = 0.025\%$ 1

International bookings: $1.4\% \times 0.5\% = 0.05\%$ 14

4

Further, in sub-rule (7D), for the figures "0.5" the words "effective rate of Swachh Bharat Cess" and for the words, figures and brackets "14 (fourteen)", the words and figures "rate of service tax specified in section 66B of the Finance Act, 1994" shall be substituted.

B. Cenvat credit of KKC to service providers only:

Amendment in Rule 3 of the Credit Rules to allow Cenvat credit of KKC to a service provider: Notification No. 28/2016 - CE (N.T.) dated May 28, 2016

The Central Government vide **Notification No. 28/2016-CE (N.T.) dated May 28, 2016**, has amended Rule 3 of the Credit Rules to provide that:

A provider of output service shall be allowed to take Cenvat credit of the KKC on taxable services leviable under Section 161 of the Finance Act, 2016 (28 of 2016);

Cenvat credit of any duty specified in Rule 3(1) of the Credit Rules shall not be utilised for payment of KKC;

Cenvat credit in respect of KKC shall be utilised only towards payment of KKC.

Thus, unlike SBCess, which is not Cenvatable neither in the hands of service providers nor manufacturers, Cenvat credit of KKC paid on input services shall be allowed to be used for payment of the KKC on taxable services provided by a service provider. Further, Cenvat credit of Service tax or Excise duty can neither be utilized for payment of KKC nor vice versa.

Manifestly, the manufacturers paying KKC on procurement of their input services would not be in a position to avail Cenvat credit of the same and thus would form part of their cost, leading to increase in prices to that extent. Thus, imposition of KKC is likely to hamper “Make in India” and “Start-up India” campaign of the Modi Government.

Treatment of KKC on on-going services/ transactions already rendered prior to June 1, 2016– Still warranting clarification

Though, the Central Government has tried to address the concerns of the assessee/industry at large to certain extent well in advance which were dragged till February, 2016 for SB Cess levied last year w.e.f. November 15, 2015. But, at the same time, the Notifications fails to amend/ clarify certain open issues on applicability of KKC on on-going transactions/ services already rendered prior to June 1, 2016, which has raised daunting concerns amongst the Trade.

With the Service tax rate (including SB Cess and KKC) of 15% becoming effective from June 1, 2016, a turmoil is being faced by the service provider in respect of on-going transactions for which completion of services have taken place before June 1, 2016 with or without raising of corresponding invoices, but payment for the same is not received till June 1, 2016.

Point of Taxation for New Levy of KKC:

It is pertinent here to note that Explanation 1 & 2 to Rule 5 of Point of Taxation Rules, 2011 (“**the POTR**”) have been inserted w.e.f March 1, 2016. Explanation 1 provides that point of taxation in case of new levy on services shall be governed by Rule 5 of the POTR and as per Explanation 2, new levy or tax shall be payable on all cases other than specified in Rule 5.

Rule 5 of the POTR covers two specific situations where new levy shall **NOT** be payable:

Invoice issued and payment received against such invoice before such service becomes taxable;

Payment received before the service becomes taxable and invoice has been issued within 14 days of the date when the service is taxed for the first time Effective June 1, 2016 KKC @ 0.5% on the value of all taxable service is proposed to be levied. Point of taxation in case of new levy on services shall be governed by Rule 5 of POTR. As per the Rule 5 read with explanations, only in two situations (mentioned above), the KKC shall not be payable and in all others, KKC is to be paid.

An illustrative table to above explanations is given as under:

S. No.	Date of applicability of KKC	Date of Invoice	Date of Payment Received	Applicability of KKC
1.	1st June, 2016	14th June, 2016	30th May, 2016	No
2.	1st June, 2016	18th June, 2016	30th May, 2016	Yes
3.	1st June, 2016	30th May, 2016	30th May, 2016	No
4.	1st June, 2016	3rd June, 2016	3rd June, 2016	Yes
5.	1st June, 2016	30th May, 2016	3rd June, 2016	Yes

Vide this explanation, the Government is seeking to impose KKC in cases, where the invoice and provision of service has taken place prior to June 1, 2016, however payment is not received till June 1, 2016. This would imply that on all debtors as on May 31, 2016, assesses will be liable to pay KKC.

Applicability of KKC when liability to pay Service tax is on Service Receiver under reverse charge POT in case of reverse charge is governed by Rule 7 of the POTR, which starts with non-obstante clause: “Notwithstanding anything contained in rules 3, 4, or 8”. In terms of Rule 7 of the POTR, point of taxation under reverse charge (except associated enterprises located outside India), shall be as under:

Payment made within 3 months – Date of payment;

Payment not made within 3 months - Date immediately following the end of 3 months

In case of associated enterprises, where the person providing the service is located outside India, POT shall be earlier of the following:

Date of debit in the books of account of service receiver;

Date of Payment

It would not be out of place here to mention that a proviso has been inserted in Rule 7 of the POTR vide Notification No. 21/2016-ST dated March 30, 2016, to provide that where there is change in the liability or extent of liability of Service tax to be paid under Reverse Charge:

Service has been provided and the invoice issued **before** the date of such change, but payment has not been made as on such date, the POT shall be **the date of issuance of invoice**.

Analyses of Erstwhile Rule 7 Vs. Amended Rule 7:

	Date of service	Date of invoice (DOI)	Date of payment (DOP)	Applicability of KKC
As per erstwhile Rule 7	20.05.2016	25.05.2016	04.06.2016	POT shall be DOP: KKC applicable
As per amended Rule 7	20.05.2016	25.05.2016	04.06.2016	POT shall be DOI: KKC not applicable

Our Comments:

Under the Finance Act, Section 66B of the Finance Act is the charging Section for levy of Service tax on taxable services. We are reproducing herewith Section 66B of the Finance Act for the ease of convenience:

“66B. Charge of service tax on and after Finance Act, 2012.

There shall be levied a tax (hereinafter referred to as the service tax) at the rate of twelve per cent. on the value of all services, other than those services specified in the negative list, provided or agreed to be provided in the taxable territory by one person to another and collected in such manner as may be prescribed.”

The literal interpretation of the charging Section 66B of the Finance Act means that the levy of Service tax is on the value of all taxable services 'provided or agreed to be provided'. However, the collection of Service tax may be shifted to any point/stage/event, in any manner, as prescribed by the Rules made in this behalf.

The Hon'ble Supreme Court in the case of **All India Federation of Tax Practitioners Vs. Union of India [2007-TIOL-149-SC-ST]** held that “a tax on a thing or goods can only be with reference to a taxable event” and the same contention was upheld again in the case of **Association of Leasing & Financial Service Companies Vs. Union of India [2010 (20) STR 417 (SC)]**, wherein the Hon'ble Supreme Court observed that the taxable event under the Service tax law is the rendition of service.

In view of the above discussed provisions, the matter is subjected to debate as to whether KKC would be leviable on a service rendered prior to June 1, 2016 when KKC was not applicable at the time of its rendition, merely because its payment is received on or after the date of levy or the invoice is not issued within 14 days of the date of levy.

Here, it would not be out of place to mention that the POTR were framed by the Central Government in exercise of the powers conferred under Section 94 of the Finance Act and such delegated legislation cannot be extended to go beyond the vires of the Finance Act.

As KKC awaits its introduction, in few days to come, still an immediate detailed clarification on the stated issue would surely be welcomed by the industry at large.

Tax Planning for KKC in terms of Rule 5 of the POTR

The explanations added to Rule 5 of the POTR raise a fundamental question as to whether a service which has already been provided prior to introduction of levy could be taxed on raising of invoice or receiving payment subsequently. However, the chargeable event being rendering of services will always be the prime factor for determining leviability of any tax or cesses. Nonetheless, the following is advised to our esteemed readers to plan their tax liability under KKC:

Service Provider:

Any payment/advance received against services provided or to be provided before June 1, 2016 - Raise Invoice within 14 days from the date of service is taxed first time i.e. June 1, 2016;

Services rendered & Invoice raised before June 1, 2016 - Collect Payment towards the invoice raised

Service Receiver:

Services rendered and No payment made before June 1, 2016 - Ask for Invoice to be raised before June 1, 2016.

To understand applicability of KKC in detail with multiple practical example(s) as to what will be the scenario when new levy 'KKC' becomes applicable from June 1, 2016 @ 0.5% on value of all taxable service, please watch video presentation at:

Hope the information will assist you in your Professional endeavours. In case of any query/ information, please do not hesitate to write back to us.

Matter Contributed by Shri Anil Mishra, J.K. Tyre & Industries Ltd, Kankroli [anilmishra@ktp.jkmail.com]

वाशवेल उद्योग समूह द्वारा बायो डीजल प्लान्ट की स्थापना

चेम्बर के सदस्य भीलवाडा साबुन उत्पादक सहकारी समिति (वाशवेल उद्योग समूह) द्वारा अपनी प्रगति पथ चितौड रोड भीलवाडा में स्थापित इकाई में 50 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता की बायो डीजल प्लान्ट की स्थापना की गई है। राजस्थान की यह पहली इकाई है। बायो डीजल के उपयोग से प्रदूषण में 70 प्रतिशत तक कमी होने की बताई गई है।

इकाई के श्री देवीलाल सोमाणी के अनुसार बायो डीजल का उपयोग सभी प्रकार के डीजल वाहन कार, जीप, ट्रैक्टर, ट्रैम्पो, टक, डम्पर, डीजी सेट के इंजन में बिना कोई परिवर्तन कराये यथा स्थिति में किया जा सकता है। या पेटोलियम डीजल में बायो डीजल 30 से 50 प्रतिशत मिलाकर उपयोग किया जा सकता है।

THE DRAFT SOLID WASTE MANAGEMENT RULES, 2015

BACKGROUND

- The draft Solid Waste Management Rules, 2015 were published by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEFCC), inviting comments and objections from stakeholders.
- In exercise of the powers conferred by sections 3, 6, and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 and in supersession of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000, the Central Government has notified new rules on 8 April 2016 for the management of Solid Waste called the Solid Waste Management Rules, 2016.

HIGHLIGHTS OF THE NOTIFIED RULES

- The ambit of the rules have been expanded beyond the Municipal areas for effective management of solid waste in other designated areas also.
- The rules shall apply to every urban local body, outgrowths in urban agglomerations, Census Towns as declared by the Registrar General and Census Commissioner of India, Notified Areas, Notified Industrial Townships, areas under the control of the Indian Railways, Airports, Airbases, Ports and Harbours, Defence Establishments, Special Economic Zones, State and Central government organisations, places of pilgrimage, religious and historical importance as may be notified by the respective State Governments from time to time and to every domestic, institutional, commercial and any other non-residential solid waste generator.
- The duties of the waste generator are clearly defined. 'Waste generator' includes every person or group of persons, every residential premises and non-residential establishments including the Indian Railways, defense establishments etc., which generate solid waste.

HIGHLIGHTS OF THE NOTIFIED RULES

- The manufacturers or brand owners or marketing companies of sanitary napkins and diapers should explore the possibility of using only recyclable materials in their products or should provide pouches or wrappers for the disposal of each napkin or diaper along with a packet of their sanitary products.
- The manufacturers of disposable products like tin, glass, plastics packaging, etc., or brand owners who introduce such products in the market should provide necessary financial assistance to the local authorities for establishing an effective system to manage waste.
- The brand owners who sell or market their products in non-biodegradable material should put in a system for collecting back the packaging waste.
- All the waste generators should wrap the used sanitary waste like diapers, sanitary pads etc. in the pouches provided by the manufacturers or brand owners of these products or in suitable wrapping material as instructed by the local authorities and should place the same in the bin meant for dry waste or non-bio-degradable waste.
- No person will be allowed to organize an event or gathering of more than one hundred persons at any unlicensed place without intimating the local body at least three days in advance. They will also have to ensure segregation of waste at source and handing over the segregated waste to a waste collector or agency as specified by the local body.
- Industrial units which are using fuel and are located within 100 km of a solid waste based refuse derived fuel plant, should make arrangements within six months from the date of notification of these rules to replace at least five percent of their fuel requirement by refuse derived fuel so produced.
- The duties of the following are clearly defined in the rules:
 - Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC)
 - Ministry of Urban Development
 - Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers
 - Ministry of Agriculture
 - Ministry of Power
 - Ministry of New and Renewable Energy Sources
 - Secretary-in-charge of Urban Development in the States and Union Territories
 - District Magistrate or District Collector or Deputy Commissioner
 - Secretary-in-charge of Village Panchayats or Rural Development Department in the State and Union Territory
 - Central Pollution Control Board (CPCB)

- Local authorities and village panchayats of census towns and urban agglomerations
- State Pollution Control Board (SPCB) or Pollution Control Committee (PCC)
- The criteria for duties regarding setting-up solid waste processing and treatment facility, the criteria and actions to be taken for solid waste management in hilly areas and the criteria for waste to energy process is elaborated in the notified rules.
- The rules also provide the timeframe for effective implementation of the provisions given in the rules.

IMPACT

- Industries involved in manufacturing or brand owners or marketing companies of sanitary napkins, diapers, and disposable products will be impacted. They will have to comply with the duties as specified in the rules for effective management of the solid waste generated by their products.
- The responsibilities of the waste generators are specified, which will ensure segregation of solid waste at the source itself.
- The concept of waste to energy will ensure effective utilization of the waste for generating energy, which will reduce the quantity of waste disposed off in the landfills.
- The integration of waste pickers or informal waste collectors will play a crucial role in the collection, segregation, recovery etc. of waste and help in the overall management of solid waste.

TAX COLLECTION AT SOURCE

Pursuant to the Finance Act, 2016, Now Tax Collection at Source (TCS) is imposed on cash sale of goods or services with effect from 1-6-2016.

Finance Act 2016 has made the following amendments in section 206C of the Act :

New Sub Section (1D) of Section 206C is as follows

Every person, being a seller, who receives any amount in **cash** as consideration for sale of bullion or jewellery or **any other goods (other than bullion or jewellery) or providing any service** shall, at the time of receipt of such amount in cash, collect from the buyer, a sum equal to **one per cent of sale consideration** as income-tax, if such consideration,—

- (i) for bullion, exceeds two hundred thousand rupees; or
- (ii) for jewellery, exceeds five hundred thousand rupees or
- (iii) for any goods, other than those referred to in clauses (i) and (ii), or any service, exceeds two hundred thousand rupees (Rs. 2,00,000)

Provided that no tax shall be collected at source under this sub-section on any amount on which tax has been deducted by the payer under Chapter XVII-B.

(in Other Words, if TDS has been deducted by the payer on payment of Goods or Services then TCS shall not be deducted by the Seller.)

Example;-

If Mr A rendered the services to Mr B for Rs 300000 and Mr B Deducted TDS on Rs 300000 before making the payment to Mr A, then Mr A is not obliged to deduct TCS of Mr B.

Analysis of Provision of TCS on cash sale of goods or services : Conditions

- ☐ Sale of any goods or any services (other than bullion or jewellery)
- ☐ Consideration for goods or services exceeds Rs. 2,00,000
- ☐ Out of such consideration, any amount is received in cash
- ☐ The seller will collect tax at the rate of 1% of sale consideration
- ☐ Tax will be collected at the time of receipt of any amount in cash.
- ☐ This Rule will be applicable irrespective of the fact whether the buyer is a manufacturer, trader or the purchase is for personal use. However, the purchaser can obtain a lower TCS certificate by submitting Form No. 13 to the Assessing Officer.

Matter Contributed by Avadesh Singhvi (CA) S.Dad & Company, Bhilwara

INDIRECT TAX DISPUTE RESOLUTION SCHEME, 2016: OVERVIEW

The Union Budget, 2016, has introduced number of measures for reducing litigation and providing certainty in taxation, considering the same as one of the key thrust areas of tax reform.

In line with said objective, the Hon'ble Finance Minister has announced Dispute Resolution Schemes for Direct and Indirect taxes for bringing down the litigation pending before the Commissioner (Appeals).

Relevant portion of Budget Speech is given as under:

“162. Litigation is a scourge for a tax friendly regime and creates an environment of distrust in addition to increasing the compliance cost of the tax payers and administrative cost for the Government. There are about 3 lakh tax cases pending with the 1st Appellate Authority with disputed amount being 5.5 lakh crores. In order to reduce this number, I propose a new Dispute Resolution Scheme (DRS)”.

Under Indirect Taxes, the scheme namely, the Indirect Tax Dispute Resolution Scheme, 2016 (**“the IDT DRS Scheme, 2016”**), introduced in the Union Budget, 2016 as the Government's positive intent to reduce litigation in Indirect Taxation, embraces an important question on its success quotient, considering its not-so-lucrative provisions.

Gist of the provisions of the IDT DRS Scheme, 2016

- ❑ The enabling provisions of the IDT DRS Scheme, 2016 are formulated in Clauses 209 to 215 under Chapter XI of the Finance Bill, 2016, which is applicable with an enactment of the Finance Bill, 2016 (Finance Bill, 2016 received assent of the President on May 14, 2016);
- ❑ It shall come into force on June 1, 2016;
- ❑ It will be applicable for all the disputes pertaining to Customs, Central Excise and Service Tax matter, which are pending before the Commissioner (Appeals) as on March 1, 2016;
- ❑ The Declarant, who want to opt for the IDT DRS Scheme, 2016 has to file a declaration to the Designated Authority in the prescribed format between the period commencing from June 1, 2016 to December 31, 2016;
- ❑ For the purpose of this Scheme, the Designated Authority means an officer not below the rank of Assistant Commissioner who is authorised to act as Assistant Commissioner by the Commissioner;
- ❑ Declaration filed by the Declarant shall be acknowledged by the Designated Authority;
- ❑ To avail the benefit of the Scheme, the Declarant will have to pay **duty/tax liability along with interest and penalty equivalent to 25% as imposed in the Impugned Order** i.e. Order-In-Original within 15 days of the receipt of the acknowledgement from the Designated Authority and intimate the Designated Authority within 7 days of such payment;
- ❑ Thereafter, Discharge Order to be passed by Designated Authority within 15 days of receipt of such proof of payment;
- ❑ After getting the Discharge Order, the appeals pending before the Commissioner (Appeals) will stand disposed off and further effect of such Order passed under the Scheme will be as under:
 1. Complete immunity from all proceedings under the respective Acts, for Excise matter under the Central Excise Act, 1944, for Service tax matter under the Finance Act, 1994 and for Customs matter under the Customs Act, 1962, and Rules made thereunder, in respect of the dispute.
 2. The Discharge Order will not be considered to be an Order on merit and will not have any binding effect.
 3. It will not be permissible for re-opening and also no refund will be granted of the amount paid under this Scheme;

Matter Contributed by Anil Mishra, J.K.Tyre & Industries Ltd,

The Bombay Textile Research Association (BTRA)

Dr. Anjan K. Mukhopadhyay has taken charge as the Director of BTRA from 1st April, 2016 in place of Dr. A.N. Desai. Dr. A.N. Desai continue to be in BTRA with the designation as Mentor.



दिनांक 25 मई 2016 को केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय श्री जयन्त सिन्हा के साथ मेवाड चेम्बर के प्रतिनिधिमण्डल की मुलाकात।



वस्त्र सचिव श्रीमति रश्मि वर्मा से मुलाकात करते हुए राज्यसभा सांसद श्री वी पी सिंह के साथ चेम्बर अध्यक्ष श्री अनिल मानसिंहका पूर्वाध्यक्ष श्री आरएल नौलखा, श्री एसएन मोदानी, डॉ पीएम बेसवाल।



20 मई 2016 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, हेम सिक्युरिटीज के सहयोग से आयोजित कार्यशाला।



मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन के तहत नितिन स्पिनर्स लि. की ओर से ग्राम पंचायत लसाडिया (शाहपुरा) में निर्मित एनिकट।



मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन के तहत आरएसडब्ल्यूएम लि की ओर से हुरडा पंचायत समिति में 4 कुओं का गहरीकरण।



With Best Compliments From :



World Class
Textile Yarn
&
Knitted Fabrics



Manufactures of

100% Cotton Yarn & Knitted Fabrics

(An ISO 9001 : 2008 Company and a Government of India Recognised Export House)



Nitin Spinners Limited

Yarn Range

- Open End Yarns From Ne. 5/1 to 30/1
- Multi Fold Open End Yarns
- Ring Spun Combed Yarns From Ne 20/1 to Ne 50/1
- Multi Fold Ring Spun Yarns
- "Z" & "S" Twist Yarns
- Dyeable Cheese Yarns
- 100% Organic Cotton Yarns & BCI Yarns
- Compact & Fancy Slub Yarns

State of Art
Manufacturing
Facility

100% Power
Backup

USTER
Standard
QC and R & D
Facility

Export to
all the
Continents

Fabrics Range

- Single Jersey Fabrics in Plain, Pique Fleece and Various Structures as per customer's requirements
- Rib Fabrics
- Interlock Fabrics
- Rib Structures
- Three Thread Fleece
- Open Width with Lycra Fabrics

16-17 Km. Stone, Chittor Road, Hamirgarh 311 025

Dist. Bhilwara (Raj.) India

Ph. : 91-1482-286110-113 Fax : 91-1482-286117

E-mail : nsi@nitinspinners.com / www.nitinspinners.com